भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 169
बुधवार, 24 जुलाई, 2024 (श्रावण 2, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों पर सेक्टर-विशिष्ट डाटा संग्रह

169 # श्री दीपक प्रकाश:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सहकारी समितियों पर सेक्टर-विशिष्ट डाटा संग्रह करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने डाटा सत्यापन और ऐसे डाटा भंडार के नियमित अद्यतनीकरण के लिए कोई प्रावधान किया है; और
(घ) डाटा भंडार से क्या अपेक्षित लाभ होंगे?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों के सहयोग से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) का निर्माण किया है । देश भर के विभिन्न क्षेत्रकों में पंजीकृत सहकारी समितियों को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के जिला पंजीयक (DRCSs) के जिला नोडल अधिकारियों द्वारा डेटाबेस में संकलित किया गया है । एनसीडी पोर्टल पर सहकारी समितियों का विस्तृत ब्यौरा यूआरएल: https://cooperatives.gov.in. पर देखा जा सकता है।

(ग): सहकारी समितियों के डेटा को राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के जिला पंजीयक (DRCSs) के कार्यालय द्वारा प्रविष्ट/अद्यतन, सत्यापित और प्रमाणित किया गया है।

(घ): राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) सहकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में अनगिनत लाभ प्रदान करता है जैसे सिंगल पॉइंट एक्सेस, व्यापक और अद्यतित डेटा, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस, वर्टिकल और हॉरिजोंटल लिंकेज, प्रश्न- आधारित रिपोर्ट व ग्राफ, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) रिपोर्ट, डेटा विश्लेषण और भौगोलिक मानचित्रण । इस पहल की सफलता प्रभावी सहभागिता, सटीक डेटा एकत्रण और क्षेत्रक कमियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस के रणनीतिक सदुपयोग और तदनुसार, उन कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त नीति निर्माण और सुविज्ञ निर्णयन पर निर्भर करता है। समग्र रूप से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पोर्टल सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।

******